Dr. Jaya
Deptt. of Sociology
B.A Part III (H)

Constituent of worker

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की कार्य समिति प्रक्रिया पर विवरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के एक भाग के रूप में कई संगठनों से नियमों और विनियमों के एक सेट का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनमें से एक खंड में कहा गया है कि कंपनी को एक कार्य समिति बनानी चाहिए। हालांकि, इसे बनाने या कार्य समिति की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

कार्य समिति क्या है?

भारत के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार, संगठन में 100 से अधिक कर्मचारी होने पर प्रत्येक नियोक्ता को एक कार्य समिति बनानी चाहिए।

कार्य समिति के सदस्यों में समान संख्या में कामगार (कर्मचारी) और नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

Scanned with CamScanner

शामिल होने चाहिए।
नियोक्ता को संघ के परामर्श से कर्मचारियों का चयन करना चाहिए।

अधिनियम निर्धारित करता है :-

किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामले में जिसमें पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन एक सौ या अधिक कामगार कार्यरत हैं, या नियोजित किए गए हैं, उपयुक्त सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियोक्ता को निर्धारित तरीके से एक कार्य समिति गठित करने की आवश्यकता कर सकती है। स्थापना में लगे नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने ताकि समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या, नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो। कामगारों के प्रतिनिधियों को भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत, उनकी ट्रेड यूनियन, यदि कोई हो, के परामर्श से स्थापना में लगे कामगारों में से निर्धारित तरीके से चुना जाएगा।

कार्य समिति प्रक्रिया की आवश्यकता

कार्य समिति प्रक्रिया की आवश्यकता दोनों पक्षों के बीच भौतिक मतभेदों को कम करने के लिए है।
यह समिति, दोनों पक्षों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच स्वस्थ संबंध बनाए रखने की देखभाल करती है। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति में सुधार करना और सामान्य शांति और काम से संबंधित मुद्दों पर काम करना है।

कार्य समिति की विशेषताएँ

1) समिति में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि नियोक्ताओं के सदस्य कर्मचारियों के सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिए।

2) नियोक्ता की ओर से प्रतिनिधियों को नियोक्ता की सहमति से चुना जाना चाहिए और इन लोगों को सीधे संगठन से जोड़ा जाना चाहिए।

3) कार्य समिति के गठन से पहले, नियोक्ता को संघ को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उनके पास एक है। इसके अलावा चुनाव के दौरान, दो समूहों का गठन किया जाना चाहिए। संघ के सदस्यों में से एक को समिति का हिस्सा बनना चाहिए चाहता है और अन्य गैर संघ सदस्य

4) समिति में जोड़े गए उम्मीदवारों को कम से कम 1 वर्ष के लिए कंपनी के साथ काम करना चाहिए था और न्यूनतम 19 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए थी।

5) समिति के सदस्यों के लिए मतदान करने वाले मतदाताओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और कंपनी में कम से कम 6 महीने तक काम किया होना चाहिए।

6) केन्द्र सरकार या समकक्ष प्राधिकरण के पास इस समिति को भंग करने का अधिकार है यदि उन्हें लगता है कि यह दिशानिर्देशों के अनुसार गठित नहीं है।

निष्कर्ष :- औद्योगिक संगठन में कार्य समिति महत्वपूर्ण है। इसलिए, इसे सरकार द्वारा निर्धारित उचित दिशानिर्देशों के साथ गठित किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner